राजस्थान राज्य

बनाम

दौड खान

(आपराधिक अपील संख्या 126/2010)

4 नवंबर, 2015

[मदन बी.लोकुर और एस.ए. बोबदे,जे. जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 304 (भाग 1)-शस्त्र अधिनियम, 1959- धारा 3 और 25 - एक व्यक्ति की मौत के लिए सज़ा - आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और धारा 25 के तहत दोषसिद्धि - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा के तहत परिवर्तित कर दिया। 302 से धारा 304 के अंतर्गत एक (भाग/)- राज्य के साथ-साथ अभियुक्त द्वारा प्रति अपीलः एफ. आई. आर. दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई-मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है-घटना के चश्मदीद गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद थे-मामले के तथ्यों पर सामूहिक रूप से विचार करने पर, अभियोजन मामले को दोगुना नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -एस. 157.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-s.157-मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी-इसका प्रभाव-आयोजितःमजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट के "तुरंत" संचार का उद्देश्य हेरफेर की संभावना की जांच करना है-यदि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट देने में देरी का कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिकी में हेरफेर को खारिज कर दिया जाएगा-कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि जब भी

मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी होती है, तो अभियोजन पक्ष का संस्करण अविश्वसनीय हो जाता है।

परीक्षण पहचान परेड-अभियोजन मामले पर प्रभाव का संचालन नहीं-आयोजितःयदि मामले के गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं, तो केवल परेड का संचालन न करना, उन गवाहों के साक्ष्य को त्यागने का कारण नहीं होगा।

न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1. यदि मामले के तथ्यों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाए, तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।सम्पूर्ण सामग्री पर विचार करने पर, आरोपी संख्या 1 द्वारा किए गए अपराध और उस अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा जाता है।[पारस 47,48] [1156-ई-एफ; 1137-डी-ई]

2. FIR दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी. घटना लगभग 9:30 बजे हुई बताई जाती है।प्राथमिकी आर. लगभग 10.30 बजे दर्ज की गई थी।प्राथमिकी आर. दर्ज करने में शायद ही कोई देरी हो। यह दलील कि एफ़. आई. आर. पूर्व-दिनांकित थी, जो एफ़. आई. आर. पर अधिलेखन से स्पष्ट है, सही नहीं है।मूल प्राथमिकी आर. में किसी भी ओवरराइटिंग की कोई झलक नहीं है। [पैरा 23,24] [1144-बी, डी-ई]

थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) 3 एस. सी. सी. 393:1972 (3) एस. सी. आर. 622-संदर्भित।

3.1 मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी आर. की एक प्रति के "तुरंत" संचार का उद्देश्य (आवश्यकतानुसार यू/एस.157 Cr.P.C.) इसके हेरफेर की संभावना की जांच करने के लिए है।इसलिए, मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी को प्राथमिकी दर्ज करने से जोड़ा जाता है। यदि एफ. आई. आर. दर्ज करने में कोई देरी नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट

को विशेष रिपोर्ट देने में किसी भी तरह की देरी का वास्तव में कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि तब एफ. आई. आर. में हेरफेर से इनकार किया जा सकता है।फिर भी, अभियोजन पक्ष को मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी के बारे में बताना चाहिए। हालांकि, अगर देरी के बारे में जांच अधिकारी से कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है।ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि जब भी मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में कुछ देरी होती है, तो अभियोजन संस्करण अविश्वसनीय हो जाता है।दूसरे शब्दों में इस संबंध में निर्णय के लिए किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं।[पैरा 26] (1145-बी-सी; 1146-ए-सी)

3.2 इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी प्राथमिकी आर. की पूर्व-तिथि या पूर्व-समय के खिलाफ बाहरी जाँचों में से एक मजिस्ट्रेट को इसे भेजने या मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी रसीद का समय है।एफ़. आई. आर. की एक प्रति "तुरंत" भेजना यह सुनिश्चित करता है कि एफ़. आई. आर. में कोई हेरफेर या हस्तक्षेप नहीं है। यदि अभियोजन पक्ष से प्राथमिकी आर. की प्रति भेजने में देरी के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए।हालाँकि, यदि अदालत अभियोजन पक्ष के बयान की सच्चाई और गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त है, तो स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है।यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।(पैरा 28] (1148-डी-ई)

3.3 वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। इसलिए इसके हेरफेर का प्रश्न ही नहीं उठता।इसके अलावा, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, पीडब्लू-21 से मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। हालांकि, जांच अधिकारी पीडब्लू-25 से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिन्होंने यह कहते हुए संक्षिप्त जवाब दिया कि अदालत (या मजिस्ट्रेट) को विशेष रिपोर्ट भेजना उनका कर्तव्य नहीं था।उस अधिकारी से, जो उत्तर दे सकता था, अर्थात् पुलिस स्टेशन

के प्रभारी अधिकारी से कोई प्रश्न पूछे जाने के अभाव में, इस संबंध में अभियोजन के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, न ही यह माना जा सकता है कि उत्तर प्राप्त होने में देरी हुई है। मजिस्ट्रेट की विशेष रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। यह चश्मदीद गवाहों के लगातार साक्ष्य के अलावा है अधिकारी यह चश्मदीद गवाहों के लगातार साक्ष्य से अलग है।(पैरा 29] (1148-एफ-जी; 1149-ए-सी]

ब्रह्म स्वरूप बनाम यू.पी.राज्य (2011) 6 SCC 288: 2010(15) एससीआर 1; शी शंकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 12 धारा 539:2013 (8) एस. सी. आर. 1100-पर निर्भर।

4. एफ. एस. एल. रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि यह किसी न किसी तरह से निर्णायक नहीं है कि मृतक के शरीर से निकाली गई गोली अपीलकर्ता-आरोपी संख्या 1 के कहने पर आरोपी संख्या 2 से बरामद पिस्तौल से चलाई गई थी या नहीं। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट अनिर्णायक थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि निकाली गई गोली बरामद बंदूक से दागे जाने में सक्षम थी।दूसरे शब्दों में, गोली और बंदूक के बीच कोई बेमेल नहीं था।[पारस 31,34] [1149-एच; 1150-; 1151-एच; 1152-डी]

मोहिंदर सिंह बनाम राज्य।1950 एससीआर 821; अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एससीसी 259:2010 (13)एससीआर 311-विशिष्ट।

5. प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि गोली अपीलार्थी-आरोपी नंबर 1 द्वारा बहुत करीब से और किसी भी घटना में दो फीट या उससे कम की दूरी से चलाई गई थी।इन परिस्थितियों में उनकी त्वचा कुछ काली पड़ गई होगी।निचली अदालत ने इसे स्वीकार किया, लेकिन यह राय थी कि चूंकि मृतक ने बनियान और शर्ट (प्रदर्शनी पी-6) पहनी हुई थी, इसलिए शायद गोली के घाव से उसकी त्वचा को काला होने से रोका गया था।

ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक की बनियान और कमीज को काला किया गया था या नहीं, और न ही इस संबंध में किसी गवाह से कोई प्रश्न पूछा गया था।इसलिए, निचली अदालत के निष्कर्ष पर विवाद करने का कोई कारण नहीं है।[पारस 36,38] [1152-एच; 1153-ए; 1154-ए-सी]

मोदी का मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सीओकोलॉजी 22 वां संस्करण पृष्ठ 354-संदर्भित।

6.1 पोस्टमॉर्टम करने वाले बोर्ड के सदस्यों में से एक पीडब्लू-14 ने कहा कि वह ऐसी परिस्थितियों में खून बहने के बारे में कोई राय नहीं दे सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगने पर खून बाहर गिर जाए। दूसरी ओर, पोस्टमॉर्टम करने वाले बोर्ड के एक अन्य सदस्य पीडब्लू-15 का मानना था कि रक्त घटना स्थल पर गिरा होगा, "लेकिन कम मात्रा में रक्त [घाव] से निकलता है जो गोली के प्रवेश के कारण होता है और बड़ी मात्रा में रक्त गोली के बाहर निकलने की चोट से निकलता है।"इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि घटना स्थल पर मृतक का खून नहीं निकला था।[पैरा 40] [1154-एफ-एच; 1155-ए]

6.2 हालांकि यह अजीब लग सकता है कि मृतक अपने सीने में गोली लेकर लगभग 70 (सत्तर) फुट की दूरी तक भाग सकता था, लेकिन यह असंभव नहीं हो सकता है।इसे समझाने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति चिकित्सा विशेषज्ञ होते, लेकिन इस संबंध में उनसे कोई प्रश्न नहीं किया गया।इन परिस्थितियों में, मृतक के सड़क पर गिरने से पहले इतनी दूरी तय करने की संभावना से इंकार करना मुश्किल है।[पैरा 41] [1155-बी-सी]

मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (1994) 5 एस. सी. सी 188-संदर्भित।

7.1 अपीलार्थी-आरोपी सं. 1 की दलीलें कि चूंकि तीन संयोग गवाह सभी शहर से बाहर के थे, वे आरोपी व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सकते थे; और क्योंकि कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी और केवल उनकी गोदी पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि न तो निचली अदालत में या न ही उच्च न्यायालय में उठाया गया था, इसलिए इस स्तर पर इस तरह के तर्क को उठाने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है।[पारस 42,43] [1155-ई-एफ]

7.2 इसके अलावा, यदि गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं, तो केवल यह तथ्य कि कोई टी. आई. पी. आयोजित नहीं किया गया था, उन गवाहों के साक्ष्य को त्यागने का एक कारण नहीं होगा।[पैरा 44] [1156-ए]

अशोक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य (2014) 4 एस. सी. सी. 747:2014 (4) एस. सी. आर. 287; कांता प्रसाद बनाम दिल्ली प्रशासन ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 350:1958 एस. सी. आर. 1218; हर्भजन सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1975) 4 एस. सी. सी. 480; जदुनाथ सिंह बनाम सी. उत्तर प्रदेश राज्य (1970) 3 एस. सी. सी. 518:1971 (2) एससीआर 917; जॉर्ज बनाम केरल राज्य (1998) 4 एससीसी 605:1998 (2) एस. सी. आर. 303; दाना यादव बनामबिहार राज्य (2002) 7 एस. सी. सी. 295:2002 (2) पूरक।एस. सी. आर. 363; मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2010) 6 एस. सी. सी. 1:2010 (4) एस. सी. आर. 103-पर निर्भर था।

7.3 वर्तमान मामले में, गोलीबारी के दो अन्य गवाह थे, जो स्थानीय निवासी थे और मृतक और आरोपी नंबर 1 को जानते थे और आसानी से उनकी पहचान कर

सकते थे।पाँच गवाहों ने घटनाओं की गवाही दी है।उनमें से किसी पर भी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि उन सभी ने घटनाओं का एक सुसंगत कथन दिया है।कुछ मामूली विसंगतियां हैं, जो होना तय है, लेकिन ये अभियोजन पक्ष के मामले के सार से दूर नहीं होती हैं और न ही वे गवाहों की विश्वसनीयता पर असर डालती हैं।[पारस 45 और 46] [1156-सी-डी]

मामला कानून संदर्भ

[1972] 3 एस. सी. आर. 622	संदर्भित	पैरा 24
[2010] 15 एस. सी. आर. 1	भरोसा किया	पैरा 26
[2013] 8 एस. सी. आर. 1100	भरोसा किया	पैरा 27
[1950] एस. सी. आर. 821	विशिष्ट	पैरा 31
(2010] 13 एस. सी. आर. 311	विशिष्ट	पैरा 34
(1994) 5 धारा 188	संदर्भित	पैरा 39
(1958) SCR 1218	भरोसा किया	पैरा 44
(2014) 4 एस. सी. आर. 287	भरोसा किया	पैरा 44
(1958) 4 धारा 480	भरोसा किया	पैरा 44
(1971) 2 एस. सी. आर. 917	भरोसा किया	पैरा 44
(1998) 2 एस. सी. आर. 303	भरोसा किया	पैरा 44
(2002) 2 सप्लीमेंट एस. सी. आर. 363	भरोसा किया	पैरा 44
(2010) 4 एस. सी. आर. 103	भरोसा किया	पैरा 44

क्रिमिनल अपील क्षेत्राधिकार : दाण्डिक अपीलीय सं 126/2010 ।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी. बी. सी. आर. एल.ए. संख्या 879/2005 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.11.2008 से।

के साथ

सी.आर.एल.ए. 2010 का नंबर 351

सुशील कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. एस. शमशेरी, ए. एएजी अमित शर्मा, यिशु प्रयास, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री प्रीति भारद्वाज, आदित्य कुमार, सूर्य कमल मिश्रा, मुश्ताक अहमद, सुश्री नमिता चौधरी उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, द्वारा पारित किया गया :

1. ये अपीलें जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 11 नवंबर, 2008 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं।राजस्थान राज्य द्वारा 2010 की दाण्डिक अपीलीय दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आई. पी. सी.) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दाऊद खान की दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई है।2010 की दाण्डिक अपीलीय सं 351 दाऊद खान द्वारा भा.दं.सं. सी. की धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. उच्च न्यायालय के फैसले की ओर ले जाने वाले व्यापक तथ्य यह हैं कि 19 जून, 2004 को लगभग 9:30 बजे नंद सिंह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में बाथरा टेलीकॉम एंड रेस्तरां गए थे।उनके साथ उनके दोस्त नितिन सिंधी (आरोपी नंबर 3) और नरेंद्र कुमावत भी थे।जब वे रेस्तरां में बैठे थे, जावेद बेग (आरोपी नंबर 2) और दाऊद खान (आरोपी नंबर 1) मोटर साइकिल पर वहां आए।ऐसा प्रतीत

होता है कि जावेद बेग और दाऊद खान को भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच के परिणाम को लेकर नंद सिंह के खिलाफ कुछ दुर्भावना थी।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, जावेद बेग ने चाकू लहराया और नंद सिंह को बताया कि आज उसका अंत हो गया है।वहाँ दाउद खान ने नंद सिंह पर उनकी छाती के दाईं ओर एक भरी हुई पिस्तौल से गोली चलाई और फिर वे दोनों अपनी मोटर साइकिल पर भाग गए।नरेंद्र कुमावत और नितिन सिंधी ने उनका पीछा किया लेकिन वे हमलावरों को पकड़ने में सफल नहीं हो सके।

4. इसके बाद, नरेंद्र कुमावत और नितिन सिंधी अपनी मोटरसाइकिल पर नंद सिंह को पास के अस्पताल ले गए, लेकिन नंद सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद नरेंद्र कुमावत नंद सिंह के आवास पर गए और अपने भाई पीडब्लू-1 गजेंद्र सिंह को घटना के बारे में सूचित किया।गजेंद्र सिंह ने भी अस्पताल का दौरा किया और फिर 19 जून, 2004 को लगभग 2 बजे निम्बाहेड़ा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। दाऊद खान और जावेद बेग को दो आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया था।

5. 21 जून, 2004 को दाऊद खान को गिरफ्तार किया गया था।इसके बाद 15 जुलाई, 2004 को जावेद बेग को गिरफ्तार कर लिया गया।नंद सिंह को गोली मारने के लिए दाऊद खान द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक जावेद खान के कब्जे से उसके कहने पर बरामद की गई थी।नितिन सिंधी को 28 जुलाई, 2007 को गिरफ्तार किया गया था।

6. तीनों व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप-पत्र दायर किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि दाऊद खान भा.दं.सं. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था,

जबकि अन्य भा.दं.सं. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 109 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे।

7. इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला और सत्र (फास्ट ट्रैक) शिविर निम्बाहेड़ा, जिला प्रतापगढ़ द्वारा 2005 के सत्र मामले के रूप में की गई थी।अपने निर्णय और आदेश में, ट्रायल जज ने दाऊद खान को भा.दं.सं. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। जावेद बेग को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था, लेकिन भा.दं.सं. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत अपराध का दोषी नहीं मिला गया था। नितिन सिंधी को किसी भी अपराध का दोषी नहीं मिला गया।आरोपी व्यक्तियों को उचित सजा सुनाई गई।

8. निचली अदालत के फैसले से व्यथित होकर दाऊद खान और जावेद बेग ने उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी और राज्य ने जावेद बेग को आंशिक रूप से दोषमुक्ति और नितिन सिंधी को पूरी तरह से दोषमुक्ति के फैसले को चुनौती दी।11 नवंबर, 2008 के अपने निर्णय और आदेश से उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दाऊद खान भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं था, बल्कि भा.दं.सं. सी. की धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के तहत उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी।जहाँ तक शस्त्र अधिनियम के तहत जावेद बेग की दोषसिद्धि का संबंध है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, लेकिन सजा को कम कर दिया गया था।उच्च न्यायालय ने जावेद बेग को भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्ति और नितिन सिंधी को पूरी तरह से दोषमुक्ति के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया।

9. दुखी महसूस करते हुए, वर्तमान अपील, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दाऊद खान और राज्य द्वारा दायर की गई हैं।

निचली अदालत का निर्णय

10. निचली अदालत के समक्ष कुछ दलीलों का आग्रह किया गया था।यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) संदिग्ध है क्योंकि अगले दिन समाचार पत्रों में यह बताया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों (अजनबियों) ने एक एस. टी. डी. बूथ में नंद सिंह की हत्या की थी।पुलिस मौके पर पहुंची और घायल (नंद सिंह) को अस्पताल ले गई।यह तर्क दिया गया कि इस संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन फिर रिकॉर्ड से हटा दी गई और दबा दी गई।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि प्राथमिकी आर. डेढ़ घंटे की देरी के बाद दर्ज की गई थी और थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य पर भरोसा किया गया था।(1972) 3 धारा 393 इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट को एफ. एल. आर. दर्ज करने के बारे में सूचित करने में काफी अस्पष्टीकृत देरी हुई थी। देरी एक दिन और 13 (तेरह) घंटे (कुल लगभग 36/37 घंटे) की सीमा तक थी।इसलिए, तथ्यों में हेरफेर करने के लिए पर्याप्त समय था ताकि आरोपी को शामिल किया जा सके।

11. यह भी तर्क दिया गया कि (जावेद से) केवल एक पिस्तौल की बरामदगी दाऊद खान को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी।किसी भी मामले में, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की राय निश्चित नहीं थी कि नंद सिंह के शरीर से निकाली गई गोली बरामद पिस्तौल से चलाई गई थी।इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि गवाहों के अनुसार, गोली बहुत दूर से चलाई गई थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में त्वचा के काले होने का संकेत नहीं दिया गया था जो कि अगर गोली बहुत दूर से चलाई गई होती।यह सुझाव देने की कोशिश की गई कि घटना के समय चश्मदीद गवाह

शायद मौजूद नहीं थे और दाऊद खान को शामिल करने के लिए एक कहानी बनाई गई थी।

12. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि घटना उस स्थान पर नहीं हुई थी जहां है हुई थी।इस तर्क के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि नंद सिंह का शव 70 (सत्तर) फुट दूर, सड़क के पार और टायर मरम्मत की दुकान के पास मिला गया था, जहां से वह कथित रूप से बाथरा टेलीकॉम में बैठे थे।जहाँ गोलीबारी हुई वहाँ कोई खून नहीं मिला, लेकिन टायर मरम्मत की दुकान के पास ही खून मिला गया।इसकी सबसे अधिक संभावना नहीं थी, विशेष रूप से जब नंद सिंह को छाती पर उनके शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास गोली मारी गई थी।इसलिए, न केवल गवाहों की उपस्थिति संदिग्ध थी, बल्कि घटना स्थल भी संदिग्ध था।

13. निचली अदालत ने समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर कोई भरोसा नहीं किया क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि संबंधित पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि अज्ञात व्यक्तियों ने अपराध किया था।निचली अदालत ने यह भी मिला कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगने वाले समय (लगभग डेढ़ घंटे) को परिस्थितियों के तहत समझाया गया था, क्योंकि नंद सिंह को अस्पताल ले जाया गया था और उनके भाई गजेंद्र सिंह (पीडब्लू-1) को घटना के बारे में सूचित करना था।देरी को अनुचित नहीं मिला गया।हालाँकि, निचली अदालत ने मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी आर. दर्ज करने के बारे में सूचित करने में देरी पर विचार नहीं किया।

14. निचली अदालत ने दाऊद खान के कहने पर जावेद से पिस्तौल के साथ-साथ अप्रयुक्त गोलियों की बरामदगी को स्वीकार कर लिया।निचली अदालत ने यह भी विचार व्यक्त किया कि एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिस्तौल से गोली चलाई गई थी और यह नहीं कहा गया था कि नंद सिंह के शरीर से निकाली गई

गोली बरामद पिस्तौल से नहीं चलाई जा सकती थी।निचली अदालत ने यह भी कहा कि नंद सिंह की त्वचा काली नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने बनियान और कमीज पहनी हुई थी।इसलिए, चश्मदीद गवाहों के बयान पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए, यह माना गया कि दाऊद खान ने नंद सिंह को घटना स्थल पर गोली मार दी थी और उस समय कई गवाह मौजूद थे।इस आधार पर, निचली अदालत ने दाऊद खान को भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया।

उच्च न्यायालय का निर्णय

15. उच्च न्यायालय के समक्ष, दाऊद खान की ओर से कुछ और विस्तृत दलीलों का आग्रह किया गया था।प्राथमिक दलीलों का आग्रह किया गया (और उन्हें हमारे सामने दोहराया गया) कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट चश्मदीद गवाहों के बयान को गलत साबित करती है।यह आग्रह किया गया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बंदूक की गोली लगभग 4 (चार) फुट की दूरी से चलाई गई थी।इसके बावजूद नंद सिंह की त्वचा का रंग काला नहीं हुआ था।उच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गवाहों ने कहा था कि 'गोली पास से चलाई गई थी' और 'किसी भी चश्मदीद गवाह ने यह नहीं कहा है कि इसे 4 फीट से कम की दूरी से दागा गया था।'दूरी में कुछ भिन्नता हो सकती है लेकिन यह दूरी के लिए घातक नहीं हो सकती है।अभियोजन का मामला।इसके अलावा, केवल इसलिए कि त्वचा का कोई कालापन नहीं था, यह अपरिहार्य निष्कर्ष नहीं निकालता है कि गोली दूर से चलाई गई थी।

16. यह निवेदन गया था कि बंदूक दाऊद खान से नहीं, बल्कि जावेद से बरामद की गई थी।उच्च न्यायालय का विचार था कि हालांकि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने दाऊद खान द्वारा जावेद को हथियार सौंपने की संभावना से इनकार नहीं किया।इस निवेदन को हमारे सामने नहीं दबाया गया था और हमें इस पर और समय बिताने की

आवश्यकता नहीं है सिवाय इस बात पर ध्यान दें के कि निचली अदालत ने मिला कि वसूली दाऊद खान के कहने पर हुई थी।

17. यह तर्क दिया गया कि अगले दिन दिखाई देने वाली समाचार रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक से प्राप्त की गई थी और इसका प्रभाव यह था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति गोलीबारी में शामिल थे।उच्च न्यायालय ने इस निवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि समाचार प्रतिनिधियों को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।इस समर्पण को हमारे सामने भी हल्के-फुल्के तरीके से पेश किया गया था, लेकिन यह किसी न किसी तरह से शायद ही निर्णायक है।

18. यह आग्रह किया गया कि नंद सिंह के खून से सना मिट्टी घटना स्थल से लगभग 70 (सत्तर) फुट दूर बरामद किया जाए।यह एक संकेत था कि शूटिंग बाथरा टेलीकॉम में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी।यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू.-1 छोटू खान में विश्वास नहीं किया, जिन्होंने कहा था कि उनकी टायर की दुकान के पास एक ट्रक से किसी ने नंद सिंह को गोली मार दी थी।उच्च न्यायालय की राय थी कि खून के धब्बे कहीं और मिला जाने का कारण यह था कि नंद सिंह गोली लगने के बाद भाग गए थे और लगभग 70 (सत्तर) फुट दूर गिर गए थे।यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू.-1 छोटू खान पर विश्वास नहीं किया, जिनके बयान को बाद में सोचा गया था।

19. अंत में यह आग्रह किया गया कि मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी (लगभग 37 घंटे के बाद) प्राप्त करने में अस्पष्ट देरी हुई।उच्च न्यायालय ने इस निवेदन पर ध्यान दिया लेकिन दुर्भाग्य से (निचली अदालत की तरह) इस पर विचार नहीं किया।

20. मामले के तथ्यों के समग्र परिप्रेक्ष्य में, दाऊद खान की ओर से प्रचार किया गया दृष्टिकोण यह था कि गोलीबारी के गवाहों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने इस विचार को खारिज कर दिया।

21. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या का मामला नहीं बनाया गया था क्योंकि दाऊद खान ने केवल एक गोली चलाई थी और स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया था और इसलिए केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे का मामला बनाया गया था जिससे मौत होने की संभावना थी, जो भा.दं.सं. सी. की धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय था। तदनुसार, दाऊद खान को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और जुर्माने के साथ 7 (सात) साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

22. दुखी महसूस करते हुए, दाऊद खान अपील में हमारे सामने है।

एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरीः प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ

23. यह निवेदन गया था कि पीडब्लू-1 गजेंद्र सिंह द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पूर्व-दिनांकित थी।वास्तव में प्राथमिकी आर. 201 जून 2004 को दर्ज की गई थी, लेकिन पहले की तारीख 191 जून 2004 थी।यह निवेदन गया था कि यह एफ. आई. आर. पर अधिलेखन से स्पष्ट है। आक्षेप यह था कि पहले आरोपी को "ठीक" करने का निराकृत गया था और फिर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।हम इस विवाद में कोई सार नहीं देखते हैं।हमने मूल रूप में प्राथमिकी आर. देखी है और किसी भी ओवरराइटिंग की कोई झलक दिखाने के लिए कुछ भी नहीं पाया है।हम यह भी ध्यान दें कर सकते हैं कि निचली अदालत या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई निवेदन नहीं किया गया था।

24. यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी। थुलिया काली और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एस. सी. सी. 1 (संविधान पीठ) का संदर्भ दिया गया था।बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब साढ़े नौ बजे हुई।प्राथमिकी आर. लगभग 10.30 बजे दर्ज की गई थी।एफ. आई. आर. दर्ज करने में शायद ही कोई 'देरी' हो। हालाँकि, यह जोड़ा जाना चाहिए कि यह तर्क इस धारणा पर आधारित था कि प्राथमिकी 20 जून 2004 को दर्ज की गई थी न कि 19 जून 2004 को, एक तर्क जिसे हम पहले ही खारिज कर चुके हैं।

सी.आर.पी.सी. की धारा 157: प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ

25. इसके बाद यह निवेदन गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी आर. प्राप्त करने में अस्पष्टीकृत देरी हुई-21 जून 2004 को लगभग 11.00 पर उन्हें प्राथमिकी आर. की प्रति प्राप्त होने के बाद से लगभग 36/37 घंटों की देरी।दाउद खान के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सी. आर. पी. सी.) की धारा 157 का उल्लंघन था, जिसमें प्राथमिकी आर. की एक प्रति (जिसे विशेष रिपोर्ट या एक स्पष्ट रिपोर्ट कहा जाता है) को तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजने की आवश्यकता होती है।157. जाँच के लिए प्रक्रिया।- (1) यदि, प्राप्त सूचना से या अन्यथा, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसी ऐसे अपराध के होने का संदेह करने का कारण है, जिसकी जांच करने के लिए वह धारा 156 के तहत सशक्त है, तो वह तुरंत पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को, जो उस पद से नीचे नहीं है, जो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्धारित करे, मौके पर आगे बढ़ने के लिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए, और यदि आवश्यक

हो, तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगाः

बशर्ते कि-(क) जब किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे किसी अपराध के होने की जानकारी नाम से दी जाती है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं होता है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने या किसी अधीनस्थ अधिकारी को मौके में जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, (ख) यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि जांच करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह मामले की जांच नहीं करेगाःबशर्ते कि बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन दर्ज करना पीड़िता के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या अभिभावक या निकट रिश्तेदारों या स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में किया जाएगा।(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उप-धारा की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन नहीं करने के अपने कारण बताएगा, और उक्त परन्तुक के खंड (ख) में उल्लिखित मामले में अधिकारी सूचना देने वाले को, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, इस तथ्य को भी सूचित करेगा कि वह मामले की जांच नहीं करेगा या इसकी जांच नहीं कराएगा।

26. सी. आर. पी. सी. की धारा 157 की व्याख्या अब एकीकृत नहीं है।इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 धारा 288 में पाई जाती है जिसमें इस विषय पर बड़ी संख्या में मामलों पर विचार मिला है। मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी आर. की एक प्रति के "तुरंत" संचार का उद्देश्य इसके हेरफेर की संभावना की जाँच करना है।इसलिए, मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी को प्राथमिकी दर्ज करने से जोड़ा जाता है। यदि एफ. आई. आर. दर्ज करने में कोई देरी

नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट देने में किसी भी तरह की देरी का वास्तव में कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि तब एफ. आई. आर. में हेरफेर से इनकार किया जा सकता है।फिर भी, अभियोजन पक्ष को मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी के बारे में बताना चाहिए।हालांकि, अगर देरी के बारे में जांच अधिकारी से कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है।ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि जब भी मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में कुछ देरी होती है, तो अभियोजन पक्ष का बयान अविश्वसनीय हो जाता है।दूसरे शब्दों में इस संबंध में निर्णय के लिए किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं।

27. शिव शंकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 12 धारा 539 के हालिया निर्णय में विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी भी चर्चा का विषय थी, जिसमें है अभिनिर्धारित किया गया था कि इस तरह के विवाद को स्वीकार करने से पहले, आरोपी को मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में देरी के कारण पूर्वाग्रह दिखाना चाहिए।यह पहले के कई निर्णयों पर निर्भर करते हुए आयोजित किया गया थाः

> "30.अपीलार्थियों की ओर से एक अन्य निवेदन यह था कि अधिकारिता मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी की प्रति अग्रेषित करने के किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 का उल्लंघन हुआ है और तब तक प्राथमिकी का पंजीकरण ही संदिग्ध हो जाता है।उक्त निवेदन को अस्वीकार करना होगा, क्योंकि अदालत के समक्ष रखी गई प्राथमिकी आर. से पता चलता है कि इसकी सूचना 4.00 p.m.13-6-1979 को दी गई थी और इसे अगले ही दिन अग्रेषित किया गया था 14-6-1979। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली निचली अदालत के विवादित फैसलों के अवलोकन से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के

कथित उल्लंघन के आधार पर अपीलार्थियों की ओर से कोई पूर्वाग्रह का मामला नहीं दिखाया गया था और न ही उठाया गया था। बार-बार, इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक आरोपी के खिलाफ गंभीर पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है, तब तक मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में केवल देरी का अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई बिगड़ता प्रभाव नहीं पड़ेगा।इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से की गई उक्त प्रस्तुति को कारित नहीं रखा जा सकता है।

31. इस संदर्भ में हम संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) ई धारा 107 में इस अदालत के हाल के एक निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें उक्त स्थिति को पैरा 62-63 में नीचे समझाया गया हैः(एससीसी p.132)

"62. अपीलार्थियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि एक्सप्रेस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को तुरंत नहीं भेजा गया जैसा कि धारा 157 सीआरपीसी के तहत निर्धारित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्राथमिकी आर. जो शुरू में 17-11-2004 पर पंजीकृत की गई थी, उसे 2004 की प्राथमिकी आर. No.116 के रूप में 19-11-2004 पर एक नंबर दिया गया था और इसे 20-11-2004 पर बदल दिया गया था और केवल 25-11-2004 पर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया गया था। जहाँ तक उक्त विवाद का संबंध है, हम केवल पाला सिंह बनाम पंजाब राज्य (1972) 2 धारा 640 में इस अदालत के रिपोर्ट किए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहते हैं जिसमें इस अदालत ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि (एस. सी. सी. पृष्ठ 645, पैरा 8) जहाँ वास्तव में बिना किसी देरी के ए. प्राथमिकी दर्ज

की गई थी और उस ए. प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी और तब अदालत के ध्यान में कोई अन्य कमजोरी नहीं लाई गई थी,संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी कितनी भी अनुचित या आपत्तिजनक क्यों न हो, आरोपी के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति में में यह स्वयं इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहरा सकता है कि जांच दूषित थी और अभियोजन पक्ष अक्षम था।

63. पाला सिंह के मामले में उपरोक्त अनुपात को लागू करते हुए, मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में देरी की ओर इशारा करते हुए, कहा गया कि उक्त देरी के कारण अपीलार्थियों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ था। जहाँ तक जाँच शुरू करने का संबंध है, हमारी पहले की विस्तृत चर्चा से पता चलता है कि उस पहलू में कोई कमी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में हम अभियोजन पक्ष के मामले में उस आधार पर कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। वास्तव में उपरोक्त निर्णय का बाद में सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 धारा 369 अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001)7 धारा 318 और अकील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 16 धारा 372 में पालन किया गया।"

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी प्राथमिकी आर. की पूर्व-तिथि या पूर्व-समय के खिलाफ बाहरी जाँचों में से एक मजिस्ट्रेट को इसे भेजने या मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी रसीद का समय है। एफ़. आई. आर. की एक प्रति "तुरंत" भेजना यह सुनिश्चित करता है कि एफ़. आई. आर. में कोई हेरफेर या हस्तक्षेप नहीं है।11 सुदर्शन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 12 एस. सी. सी. 312 यदि अभियोजन पक्ष से प्राथमिकी आर. की प्रति भेजने में देरी के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए। मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994)5 एससीसी 188।

हालाँकि, यदि अदालत अभियोजन पक्ष के बयान की सच्चाई और गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त है, तो स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।रतिराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2013) 12 धारा 316।

29. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। इसलिए इसके हेरफेर का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, पीडब्लू-21 सुरेंद्र सिंह से मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। हालांकि, जांच अधिकारी पीडब्लू-25 राजिंदर पारिक से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिन्होंने यह कहते हुए संक्षिप्त जवाब दिया कि अदालत (या मजिस्ट्रेट) को विशेष रिपोर्ट भेजना उनका कर्तव्य नहीं था। उस अधिकारी से, जो उत्तर दे सकता था, अर्थात् पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से कोई प्रश्न न पूछे जाने पर, इस संबंध में अभियोजन के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, न ही यह माना जा सकता है कि इसमें देरी हुई है। मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रिपोर्ट की प्राप्ति अभियोजन के मामले के लिए घातक है। यह चश्मदीद गवाहों के लगातार साक्ष्य से अलग है, जिस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। यह चश्मदीद गवाहों के सुसंगत साक्ष्य के अलावा है, जिसका हम थोड़ी देर बाद विज्ञापन करेंगे।

बैलिस्टिक रिपोर्टःप्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ

30. यह जोरदार तर्क दिया गया कि एफएसएल (प्रदर्शनी पी-37) की रिपोर्ट में निर्णायक रूप से यह नहीं कहा गया है कि नंद सिंह के शरीर से बरामद गोली दाऊद खान के कहने पर जावेद से बरामद ओपिस्टल से चलाई गई थी।एफ. एस. एल. रिपोर्ट इस प्रकार हैः

"1. एक.32 पैकेट 'E' से देश में बनी रिवॉल्वर (W/1) एक उपयोगी आग्नेयास्त्र है।हालाँकि, इसमें गोला-बारूद को गलत तरीके से चलाने की प्रवृत्ति है।

2. बैरल अवशेषों की जांच से पता चलता है कि प्रस्तुत एक.32 देशी रिवॉल्वर (डब्ल्यू/1) से गोली चलाई गई थी। हालाँकि, इसके अंतिम फायर का निश्चित समय उतना निश्चित नहीं हो सका।

3. स्टीरियो और माइक्रोस्कोपिक जाँच के आधार पर, यह राय है कि पैकेट 'ई' और एक से निश्चित रूप से एक 7.65 मिमी कार्ट्रिज केस (सी/1) को जोड़ना संभव नहीं है।।'डी' ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पैकेट 'ई' से एक .32 रिवॉल्वर (डब्ल्यू/1) जमा किया। "

31. एफएसएल रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि यह किसी न किसी तरह से निर्णायक नहीं है कि नंद सिंह के शरीर से निकाली गई गोली दाऊद खान के कहने पर जावेद से बरामद पिस्तौल से चलाई गई थी या नहीं।इसे ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने मोहिंदर सिंह बनाम पर भरोसा रखा।राज्य 1950 एससीआर 821।उस मामले के तथ्य काफी अनोखे थे।कहा जाता है कि मृतक दलीप सिंह को दो चोटें आईं, एक अपीलार्थी-मोहिंदर सिंह द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक से उनकी छाती पर लगी और दूसरी उनके कान के पास, जब वह बगल में लेटा हुआ था, जिस पर वर्णम सिंह ने लगभग 4 से 5 फुट की दूरी से राइफल से वार किया।अभियोजन पक्ष के निश्चित मामले के अनुसार, अपीलार्थी-मोहिंदर सिंह ने बंदूक से गोली चलाई थी, लेकिन इस अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसने महसूस किया कि अपीलार्थी-मोहिंदर सिंह को लगी चोट एक राइफल के कारण हुई थी।दूसरे शब्दों में, हथियार और गोली के बीच एक बेमेल था।इस संदर्भ में, इस अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"एक ऐसे मामले में जहां मृत्यु एक घातक हथियार के कारण हुई चोटों या घावों के कारण होती है, यह हमेशा अभियोजन पक्ष का कर्तव्य माना गया है कि वह विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि यह संभवतः या कम से कम संभव था कि चोटें उस हथियार के कारण हुई थीं जिससे और जिस तरीके से उन्हें कथित रूप से किया गया था।यह प्राथमिक है कि जहां अभियोजन पक्ष का कोई निश्चित या सकारात्मक मामला है, उसे उस पूरे मामले को साबित करना होगा।वर्तमान मामले में, यह संदेह है कि अपीलकर्ता (मोहिंदर सिंह) को जो चोटें लगी हैं, वे बंदूक से लगी हैं या राइफल से।वास्तव में यह अधिक संभावना प्रतीत होती है कि वे बंदूक की तुलना में राइफल से किए गए थे, और फिर भी अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता बंदूक से लैस था, और उसकी जाँच में यह निश्चित रूप से कहा गया था कि वह बंदूक पी-16 से लैस था।यह केवल एक विधिवत योग्य विशेषज्ञ के साक्ष्य से ही पता चल सकता था कि क्या अपीलकर्ता को लगी चोटें बंदूक या राइफल से लगी थीं और केवल ऐसे साक्ष्य से ही इस विवाद का निपटारा हो सकता था कि क्या वे संभवतः इतनी निकट दूरी पर आग्नेयास्त्र के उपयोग के कारण हुए थे जैसा कि साक्ष्य में सुझाव दिया गया है।"

32. और, उस मामले में विशेषज्ञ की क्या राय थी? इस अदालत ने नोट किया कि निदेशक, सी. एल.डी. ब्लैबोरेटरी, फिलौर का सारांश निम्नलिखित शब्दों में दिया जा सकता हैः

"बंदूक पर गोली चलने के संकेत थे लेकिन वह (विशेषज्ञ) यह नहीं बता सके कि इसे आखिरी बार कब दागा गया था।कार्ट्रिज केस पी-10

और पी-15 को बंदूक पी-16 के माध्यम द्वारा दागा जा सकता था, लेकिन वह यह नहीं बता सके कि क्या वे वास्तव में उस विशेष बंदूक या इसी तरह की बंदूक या बंदूक द्वारा दागे गए थे।उन्होंने बंदूक पी-16 से कोई काट्रिज दागकर कोई प्रयोग नहीं किया, न ही उन्होंने खाली काट्रिज पी-10 और पी-15 पर निशानों की तुलना की।"

33. इस आधार में, यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक-दलीप सिंह में दो गोलियां चलाई गईं और "एक महत्वपूर्ण बिंदु जो अभियोजन पक्ष ने साबित किया था, वह यह था कि ये गोलियां दो व्यक्तियों द्वारा चलाई गई थीं, न कि एक व्यक्ति द्वारा, और दोनों गोलियां इस तरह से और इतनी दूरी से चलाई गई थीं, जैसा कि चश्मदीद गवाहों द्वारा आरोप लगाया गया है।हमारी राय में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में सबसे बुनियादी बिंदु पर अंतर है और निचली अदालतों द्वारा की गई त्रुटि अंतर को नजरअंदाज करना है।" अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में इस अंतर को देखते हुए, इस अदालत ने अपीलकर्ता-मोहिंदर सिंह को संदेह का लाभ दिया।इसके अलावा, इस अदालत ने तीन चश्मदीद गवाहों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उनमें से दो संयोग गवाह थे और "पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति नहीं थे" जबकि तीसरा एक पक्षपातपूर्ण गवाह था और उसकी गवाही अन्यथा असंभव थी क्योंकि उसने खुद को गोली मारने के बाद गोलीबारी देखी थी।

34. जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, मामले के तथ्य काफी अलग हैं। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट ए इस मायने में अनिर्णायक थी कि यह नहीं कहा जा सकता था कि निकाली गई गोली 'निश्चित रूप से' बरामद किए गए हथियार से जुड़ी हो सकती है या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि निकाली गई गोली बरामद बंदूक से दागे जाने में सक्षम थी।दूसरे शब्दों में (और यह महत्वपूर्ण है) गोली और बंदूक के बीच कोई बेमेल नहीं था।इसलिए मोहिंदर सिंह दाऊद खान की सहायता के

लिए नहीं आता है।हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता ने अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 धारा 259 में भरोसा करके निश्चितता की अनुपस्थिति में को भुनाने की कोशिश की, लेकिन उस निर्णय की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

उस मामले में चिकित्सा साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य के बीच टकराव था; जबकि इस मामले में ऐसा कोई टकराव नहीं है।विषयगत और नेत्र साक्ष्य दोनों से कोई संदेह नहीं है कि दाऊद खान ने बंदूक से गोली चलाई थी।फोरेंसिक साक्ष्य से पता चलता है कि नंद सिंह के शरीर से निकाली गई गोली बरामद बंदूक से दागे जाने में सक्षम थी।नंद सिंह को बरामद बंदूक या किसी अन्य बंदूक से गोली मारी गई थी या नहीं, इस पर प्रश्न नहीं उठाया गया और किसी भी गवाह से दाऊद खान के कहने पर जावेद से बरामद बंदूक के बारे में कोई ठोस प्रश्न नहीं पूछा गया या क्या यह वही बंदूक (या एक अलग) थी जिसका इस्तेमाल दाऊद खान ने किया था।त्वचा का काला पड़नाःप्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ

35. यह तर्क दिया गया था कि चूंकि नंद सिंह को बहुत दूर से गोली मारी गई थी, इसलिए उनकी त्वचा पर कुछ कालापन होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई कालापन नहीं दिखाया गया था।इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि नंद सिंह को वास्तव में कहीं और गोली मारी गई थी (जहां वह गिर गया था) न कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए स्थान पर।

36. पीडब्लू-11 नरेंद्र कुमावत, जो नंद सिंह के साथ थे और घटना के समय उनके साथ थे, ने कहा कि दाऊद खान ने लगभग दो फुट की दूरी से गोलीबारी की थी। इसी तरह, पीडब्लू-19 सूरज मल ने कहा कि गोली दो फुट की दूरी से चलाई गई थी, जबकि पीडब्लू-7 महाबीर सिंह ने कहा कि अतत को एक फुट की दूरी से चलाई गई थी।पीडब्लू-23 नरेंद्र सिंह ने कहा कि गोली 'चार उंगलियों की दूरी से चलाई गई थी

और गोली पिस्तौल को सीने से छूते हुए नहीं चलाई गई थी।'अंत में, पीडब्लू-24 ऋषि राज शेखावत ने कहा कि "नंद सिंह, ब्राथर की छाती को छूने के बाद आग नहीं लगाई गई थी, यह एक या दो फुट की दूरी से चलाई गई थी"।इसलिए, प्रत्येक चश्मदीद ने कहा कि दाऊद खान ने नंद सिंह पर बहुत करीब से और किसी भी घटना में दो फीट या उससे कम की दूरी से गोली चलाई थी।उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से मिला कि गवाहों ने गवाही दी थी कि गोलीबारी पास से हुई थी, लेकिन किसी भी गवाह ने किसी दूरी का उल्लेख नहीं किया था।

37. जो भी हो, इस स्तर पर, मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के 22 वें संस्करण के पृष्ठ 354 का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें बंदूक की गोली के घाव में त्वचा के काले होने के संदर्भ में उल्लेख किया गया हैः

> "यदि एक बन्दूक को शरीर के बहुत करीब या वास्तविक संपर्क में छोड़ा जाता है, तो प्रवेश द्वार के घाव के चारों ओर दो या तीन इंच के क्षेत्र में त्वचीय ऊतकों को चीर दिया जाता है और आसपास की त्वचा को आमतौर पर धुएँ से जला दिया जाता है और काला कर दिया जाता है और बिना जले हुए दाने के बारूद या धुएँ रहित प्रणोदक पाउडर के साथ टैटू किया जाता है।आस-पास के बालों को गाया जाता है, और उस हिस्से को ढकने वाले कपड़ों को लौ से जला दिया जाता है।यदि पाउडर धुआं रहित है, तो घाव के आसपास की त्वचा पर धूसर या सफेद जमा हो सकता है।यदि क्षेत्र को अवरक्त प्रकाश द्वारा खींचा जाता है, तो घाव के चारों ओर एक धुएँ का प्रभामंडल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।यदि बन्दूक जैसी बन्दूक को तीन फुट से अधिक की दूरी से नहीं छोड़ा जाता है और एक

रिवॉल्वर या पिस्तौल को लगभग दो फुट के में छोड़ा जाता है, तो ब्लैकनिंग मिला है।"

38. इन परिस्थितियों में पूरी संभावना है कि अगर नंद सिंह को वास्तव में लगभग दो फीट या उससे कम की दूरी से गोली मारी गई होती, तो उनकी त्वचा कुछ काली हो जाती।निचली अदालत ने इसे स्वीकार किया लेकिन उनकी राय थी कि चूंकि नंद सिंह ने बनियान और शर्ट (प्रदर्शनी पी-6) पहनी हुई थी, इसलिए शायद बंदूक की गोली के घाव से उनकी त्वचा को काला होने से रोका गया था।ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि नंद सिंह की बनियान और कमीज को काला किया गया था या नहीं, और न ही इस संबंध में किसी गवाह से कोई प्रश्न पूछा गया था।इसलिए, हमारे पास निचली अदालत के निष्कर्ष पर विवाद करने का कोई कारण नहीं है।

रक्त मार्गःप्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ

39. दाऊद खान के विद्वान अधिवक्ता ने एक अजीब परिस्थिति का उल्लेख किया, जो यह है कि नंद सिंह सीने में गोली लगने के बाद लगभग 70 (सत्तर) फुट की दूरी पैदल तय करने में कामयाब रहे।इस दूरी के दौरान, कोई रक्त का निशान नहीं था, न ही घटना स्थल पर कोई रक्त गिरा था।मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 5 धारा 188 में घटना के स्थान पर रक्त की अनुपस्थिति में या घटना के स्थान से उस स्थान तक कोई रक्त का निशान जहां शव मिला गया था, इस अदालत को (अन्य बातों के साथ) अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया।

40. हालाँकि, इस मामले में दर्ज साक्ष्य इस संबंध में कोई संदेह नहीं अनुमति हैं।पीडब्लू-14 डॉ. तेज सिंह डांगी (पोस्टमॉर्टम करने वाले बोर्ड के सदस्यों में से एक) ने

कहा कि वह ऐसी परिस्थितियों में खून बहने के बारे में कोई राय नहीं दे सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगने पर खून बाहर गिर जाए।दूसरी ओर, पीडब्लू-15 डॉ. के. आसिफ (पोस्टमॉर्टम करने वाले बोर्ड के एक अन्य सदस्य) का मानना था कि रक्त घटना स्थल पर गिरा होगा, "लेकिन कम मात्रा में रक्त [घाव] से निकलता है जो गोली के प्रवेश के कारण होता है और बड़ी मात्रा में रक्त गोली की निकास चोट से निकलता है।"इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि घटना स्थल पर नंद सिंह का खून नहीं निकला था।

41. यह रिकॉर्ड में आया है कि नंद सिंह एक युवा बैंड स्वस्थ व्यक्ति थे। हालांकि यह अजीब लग सकता है कि वह अपनी छाती में एक गोली के साथ लगभग 70 (सत्तर) फुट की दूरी तय कर सकते थे, लेकिन यह असंभव नहीं हो सकता है।इसे समझाने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति चिकित्सा विशेषज्ञ होते, लेकिन इस संबंध में उनसे कोई प्रश्न नहीं किया गया।इन परिस्थितियों में, इस संभावना से इंकार करना मुश्किल है कि नंद सिंह ने सड़क के पार गिरने से पहले दूरी तय की थी।

डॉक पहचानःप्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ

42. दाउद खान ने तर्क दिया कि तीन संयोग गवाह, पीडब्लू-7 महाबीर सिंह, पीडब्लू-23 नरेंदर सिंह और पीडब्लू-24 ऋषि राज शेखावत सभी शहर से बाहर के थे। इस प्रकार, वे दाऊद खान या जावेद की पहचान नहीं कर सकते थे।यह आगे तर्क दिया गया कि कोई परीक्षण पहचान परेड (संक्षिप्त टी. आई. पी. के लिए) आयोजित नहीं की गई थी और केवल उनकी गोदी पहचान पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती थी।

43. दाऊद खान ने न तो निचली अदालत में और न ही उच्च न्यायालय में ऐसा कोई तर्क दिया था और हम इस स्तर पर इस तरह के तर्क को उठाने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

44. इसके अलावा, अशोक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य (2014) 4 धारा 747 में हाल ही में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि एक मुकदमे में एक आरोपी की पहचान का साक्ष्य के एक ठोस टुकड़े के रूप में स्वीकार्य है, यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या इस तरह के साक्ष्य के टुकड़े पर किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र आधार के रूप में भरोसा किया जा सकता है या नहीं।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "यदि गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं, तो केवल यह तथ्य कि कोई टी. आई. पी. आयोजित नहीं किया गया था, उन गवाहों के साक्ष्य को त्यागने का एक कारण नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, इस अदालत ने कई निर्णयों पर भरोसा किया।कांता प्रसाद बनाम दिल्ली प्रशासन, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 350, हर्भजन सिंघव बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1975) 4 एस. सी. सी. 480, जदुनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1970) 3 एस. सी. सी. 518, जॉर्ज बनाम केरल राज्य, (1998) 4 एस. सी. सी. 605 और दाना यादव बनाम बिहार राज्य, (2002) 7 एस. सी. सी. 295 में इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था।

इससे पहले, मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। (2010) 6 धारा 1, अनुच्छेद 255 से 258 तक।

45. किसी भी घटना में, गोलीबारी के दो अन्य गवाह थे, अर्थात् पीडब्लू-11 नरेंदर कुमावत और पीडब्लू-19 सूरज मल जो स्थानीय निवासी थे और नंद सिंह और दाऊद खान को जानते थे और आसानी से उनकी पहचान कर सकते थे।

46. 19 जून 2004 की रात को बाथरा टेलीकॉम में हुई घटनाओं के बारे में पांच गवाहों ने गवाही दी है। हम उनमें से किसी पर भी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, विशेष रूप से क्योंकि उन सभी ने घटनाओं का एक सुसंगत कथन दिया

है। कुछ मामूली विसंगतियाँ हैं, जो वहाँ होना तय है, जैसे कि बंदूक और नंद सिंह के बीच की दूरी लेकिन ये अभियोजन पक्ष के मामले के सार से दूर नहीं होती हैं और न ही वे गवाहों की विश्वसनीयता पर असर डालती हैं।

निष्कर्ष

47. यदि मामले के तथ्यों को व्यक्तिगत रूप से और यादृच्छिक रूप से देखा जाता है, तो वे संदेह पैदा कर सकते हैं।हालाँकि, यदि उन पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है, तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।सामूहिक रूप से तथ्य इस प्रकार हैंः(i) नंद सिंह को बंदूक से गोली मार दी गई थी।(ii) नंद सिंह के शरीर से निकाली गई गोली उस बंदूक से चलाई जा सकती थी, या नकारात्मक रूप से कहें तो यह नहीं कहा जा सकता है कि निकाली गई गोली बरामद बंदूक से नहीं चलाई जा सकती थी। इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया।(iii) बंदूक की गोली बहुत दूर से चलाई गई थी, लेकिन संभवतः उनके परिधान के कारण नंद सिंह की त्वचा पर कोई काला रंग नहीं आया था।इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया।(iv) नंद सिंह की मृत्यु तत्काल नहीं हुई थी और गोली लगने के बावजूद वह लगभग 70 (सत्तर) फुट की दूरी तय कर सकते थे। इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया।(v) चिकित्सा विशेषज्ञों ने गवाही दी कि प्रवेश घाव से खून का रिसाव अपरिहार्य नहीं है और इसलिए यह संभव है कि नंद सिंह का खून घटना के स्थान और उस स्थान के बीच नहीं मिला जहां वह गिर गया था।हालाँकि, जहाँ नंद सिंह गिरे थे, वहाँ खून मिला गया था।(vi) गोलीबारी की घटना के पांच चश्मदीद गवाह थे और उन्होंने लगातार बयान दिए और नंद सिंह को गोली मारने वाले व्यक्ति के रूप में दाऊद खान की पहचान की।इनमें से कोई भी निष्कर्ष और निष्कर्ष विकृत नहीं हैं।इसके विपरीत, उन्हें निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

48. हमारे सामने पूरी सामग्री पर विचार करने पर, हमें दाऊद खान द्वारा किए गए अपराध और उस अपराध के लिए उसकी सजा के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बनाए रखने में कोई संकोच नहीं है।हम राज्य द्वारा दायर अपील में कोई सार नहीं देखते हैं और दाऊद खान द्वारा किए गए अपराध के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्षों को उलटने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

49. दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।